भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3822

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की समीक्षा

3822. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को तमिलनाडु सहित राज्य-वार कुल कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) जारी किए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी बार मृदा परीक्षण किए गए हैं और इनकी कवरेज कितनी है और मृदा परीक्षण के परिणामों के आधार पर कितने किसानों को सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने, इनके नवीकरण या सटीकता में कमियां पाई हैं;

(घ) इष्टतम उर्वरक अनुप्रयोग और मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मृदा पोषक तत्वों के उपयोग के बारे में किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या मृदा स्वास्थ्य आयोगों की सिफारिशों को अपनाते हुए किसानों को कोई अनुवर्ती सहायता, प्रशिक्षण अथवा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है; और

(च) सभी राज्यों में डिजिटल ट्रैकिंग, प्रयोगशाला अवसंरचना और एसएचसी की समय पर सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर के किसानों को 26.26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) जारी किए गए हैं। तमिलनाडु सहित राज्यवार एसएचसी जारी करने का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। इस योजना के तहत, कुल 8313 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (1267 स्टैटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 168 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 6197 लघु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा 681 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं) स्थापित की गई हैं। पिछले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान, 2.42 करोड़ मृदा परीक्षण किए गए हैं और देश भर के लघु एवं सीमांत किसानों को 2.42 करोड़ एसएचसी जारी/सृजित किए गए हैं।

(घ) से (ङ): इस योजना के अंतर्गत, किसानों को एसएचसी में दी गई अनुशंसाओं का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए लगभग 7.17 लाख प्रदर्शन, 130627 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम और 7,425 किसान मेले आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एसएचसी के उपयोग और अन्य मुद्दों में किसानों की सहायता के लिए 70,002 कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया गया है। विद्यालय मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 2023-24 में आरंभ किया गया था, जिसमें छात्रों द्वारा मृदा नमूना संग्रह, परीक्षण, एसएचसी निर्माण और किसानों को

सलाह देने में भाग लिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बच्चों और उनके परिवारों में एसएचसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों में 2015 मृदा प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। एसएचसी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के लिए विशिष्ट सलाह भी प्रदान करता है। वर्ष 2025-26 से अब तक, प्राकृतिक किसानों के 19.37 लाख मृदा नमूने एकत्र किए गए हैं तथा उनमें से 14.57 लाख एसएचसी तैयार किए गए हैं। कृषि की लाभार्थी-संबंधित योजनाएँ जिनमें 'खाद्य तेल-तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन' और 'दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन' शामिल हैं, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) बनवाने और उसमें दी गई सलाहों का पालन करने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं।

ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (आरएडब्ल्यूई) कार्यक्रम, जो छात्र रेडी (आरईएडीवाई) (ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना) का एक घटक है, कृषि स्नातक छात्रों को गांवों और खेती का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। ये छात्र, विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करते हैं। वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक, इस कार्यक्रम में 62 कृषि विश्वविद्यालयों के 1,05,329 स्नातक छात्रों को शामिल किया गया। इन प्रौद्योगिकियों में कम लागत वाली प्रौद्योगिकियां जैसे येलो स्टिकी ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स, बीज उपचार, वर्मीकम्पोस्टिंग, एकीकृत कृषि प्रणाली आदि शामिल हैं। इन सभी विस्तार गतिविधियों का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों द्वारा एसएचसी जारी करना, उनका नवीनीकरण करना तथा उनके उपयोग में मौजूद कमियों को दूर करना है। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना, एसएचसी की लागत को कवर करती है तथा यह किसानों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। सरकार प्रत्येक एसएचसी के निर्माण के लिए 300 रुपये की धनराशि का व्यय करती है और यह किसानों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। एसएचसी की सिफारिशों को अपनाने वाले किसानों को कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

(च): नमूना एकत्र करने के बाद किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल के माध्यम से संचालित नंबर दर्ज करके एसएचसी के निर्माण को डिजिटल रूप से https://soilhealth.dac.gov.in/soilhealthcard पर ट्रैक कर सकता है। एसएचसी सृजित होने के बाद, इसे पोर्टल से डाउनलोड भी किया जा सकता है। इस योजना के तहत राज्यों को मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्टैटिक/मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए प्रति प्रयोगशाला 75 लाख रुपये और ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 1.5 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत, कुल 8313 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (1267 स्टैटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 168 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 6197 लघु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा 681 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं) स्थापित की गई हैं। किसानों को समय पर एसएचसी उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 25.10.2023 को नागरिक चार्टर तैयार करके जारी किया गया है। नागरिक चार्टर के अनुसार, मृदा नमूना संग्रह, परीक्षण, एसएचसी तैयार करना और किसानों को सिफारिशें जारी करने की पूरी प्रक्रिया, नमूना संग्रह के 25 दिनों के भीतर (पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 30 दिनों के भीतर) पूरी की जानी चाहिए।

अनुबंध- I

<u>वर्ष 2014-15 से अब तक, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के अंतर्गत जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों का राज्यवार विवरण।</u>

(संख्या में)

क्र.स.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	किसानों को जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार	53548
2	आंध्र प्रदेश	16247087
3	अरुणाचल प्रदेश	217606
4	असम	4402295
5	बिहार	15824822
6	छत्तीसगढ़	10160966
7	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	15797
8	गोवा	92587
9	गुजरात	15359628
10	हरियाणा	10411716
11	हिमाचल प्रदेश	1639073
12	जम्मू-कश्मीर	2288059
13	झारखंड	1569112
14	कर्नाटक	18099620
15	केरल	3569784
16	लद्दाख	5575
17	मध्य प्रदेश	21382112
18	महाराष्ट्र	28523314
19	मणिपुर	253318
20	मेघालय	529395
21	मिजोरम	99926
22	नागालैंड	478954
23	ओडिशा	6386575
24	पुदुचेरी	46221
25	पंजाब	3108467
26	राजस्थान	20439948
27	सिक्किम	210453
28	तमिलनाडु	15621730
29	तेलंगाना	11242403
30	त्रिपुरा	411011
31	उत्तर प्रदेश	41184919
32	उत्तराखंड	2020485
33	पश्चिम बंगाल	10739004
कुल		**262635510**

स्रोत: एसएचसी पोर्टल

******